रिविजनल सिविल

हरबंस सिंह, मुख्य न्यायमूर्ति, के समक्ष ।

गुरमुख सिंह, - *याचिकाकर्ता*

बनाम

दलीप सिंह, आदि, - उत्तरदाता

सी.आर., 1970 की संख्या 1170.

29 जनवरी, 1971

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम V) - धारा 115 और आदेश *6* नियम *17* - पंजाब पूर्व-अनुभव अधिनियम (*1913* का I) - धारा *15* - *विक्रेता के साथ संबंध के आधार पर भूमि के पूर्व-अधिग्रहण के लिए मुकदमा - मुकदमे के लिए सीमा की समाप्ति के बाद, वादी ने वाद में संशोधन की मांग की ताकि भूमि में सह-हिस्सेदार होने के पूर्व-अनुभव का नया आधार पेश किया जा सके - ऐसा संशोधन - क्या होना चाहिए। वाद के लिए सीमा की अवधि के बाद पूर्व-अनुभव का नया आधार पेश करने के लिए वाद में संशोधन की अनुमति देने वाला आदेश - ऐसा आदेश - क्या धारा 115 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित किया जा सकता है*।.

यह माना गया कि जहां एक वादी विक्रेता के साथ अपने संबंधों के आधार पर भूमि के पूर्व-अधिग्रहण के लिए मुकदमा दायर करता है, और फिर सीमा की अवधि की समाप्ति के बाद- वाद के लिए वाद में संशोधन की मांग की जाती है ताकि बेची गई भूमि में सह-हिस्सेदार होने के पूर्व-अनुभव का एक नया आधार पेश किया जा सके, तो इस तरह के संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मूल रूप से लिये गये आधार और उस आधार के बीच कोई संबंध नहीं है जिसे जोड़ने की मांग की गई है। यह पहले से लिए गये आधारों को समझाने का प्रयास भी नहीं है। मूल रूप से दावा केवल संबंध के आधार पर किया जाता है और इस बात पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि, यदि वह संबंध साबित नहीं होता है, तो वादी का मुकदमा विफल होना तय है, लेकिन, यदि संशोधन की अनुमति दी जाती है, तो, भले ही वादी रिश्ते के सवाल पर विफल हो जाता है, वह सह-हिस्सेदार होने के दूसरे आधार पर वापस आ सकता है जिसे वह सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद पहली बार ले रहा है। इसलिए वादी द्वारा सीमा की अवधि के

बाद सह-हिस्सेदार होने के नए आधार को पेश करने के लिए मांगे गए संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। (पैरा 13)

यह माना गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत संशोधन की अनुमति देने या अस्वीकार करने का सवाल न्यायालय के साथ विवेकाधिकार का मामला है और, यदि उस विवेक ाधिकार का न्यायिक रूप से प्रयोग किया गया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उस विवेकाधिकार के प्रयोग में अधिकार क्षेत्र की कोई कमी रही है या अधिकार क्षेत्र का उपयोग अनियमित या अवैध तरीके से किया गया है और इस प्रकार उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर कार्रवाई का एक नया कारण या पूर्व-मूल्यांकन के लिए मुकदमे को बनाए रखने के लिए एक नया आधार जोड़ने और जोड़ने की अनुमति दी गई है, तो उस समय जब उस आधार पर लाया गया एक नया मुकदमा समय तक निराशाजनक रूप से रोक दिया गया होगा, तो इसे न्यायिक तरीके से विवेक का प्रयोग नहीं कहा जा सकता है, और इसलिए न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर कार्य करने के लिए लिया जाना चाहिए। इसलिए संशोधन की अनुमति देने का ऐसा आदेश संहिता की धारा 115 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित किया जा सकता है। (स्तर 7 और 9)

अधिनियम 1908 की धारा 115 सी.पी.सी. के तहत श्री पीसी नरियाला, अतिरिक्त उप न्यायाधीश द्वितीय वर्ग, सिरसा, जिला हिसार के 31 अगस्त 1970 के आदेश में संशोधन के लिए याचिका, जिसमें वादी को 30 रुपये की लागत के भुगतान पर वाद में संशोधन करने की अनुमति दी गई थी।

के. एल जग्गा, वकील, याचिकाकर्ता के लिए

एच.एस. गुजराल, वकील, प्रतिवादियों के लिए

निर्णय।

हरबंस सिंह, मुख्य न्यायमूर्ति -(1) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 (इसके बाद संहिता के रूप में संदर्भित) के तहत यह संशोधन निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ है:

2. दलीप सिंह नाम के एक व्यक्ति ने विक्रेता तेजा सिंह द्वारा बेची गई संपत्ति को कब्जे में लेने के लिए अग्रक्रय अधिकार के आधार पर मुकदमा दायर किया। संबंध के आधार पर बेहतर अधिकार का दावा किया गया था, और यह दावा किया गया था कि अग्रक्रय अधिकार रखने वाला व्यक्ति विक्रेता के भाई का बेटा था।. मुकदमा लंबित रहने के दौरान वादी दलीप सिंह की मृत्यु हो गई। उनके कानूनी प्रतिनिधि बच्चे होने के नाते रिकॉर्ड पर लाए जाने के लिए आवेदन करते हैं। इस

आवेदन को स्वीकार कर लिया गया और कानूनी प्रतिनिधियों को संशोधित वाद दायर करने का निर्देश दिया गया, जिसे 3 जुलाई 1970 को दायर किया गया था। यहां यह कहा जा सकता है कि मुकदमा 26 जून 1968 को स्थापित किया गया था।

3. 22 जुलाई 1970 को, कानूनी प्रतिनिधियों (इसके बाद वादी के रूप में संदर्भित) ने संहिता के आदेश VI, नियम 17 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें निम्नलिखित प्रभाव के लिए वाद के पैराग्राफ 4 में एक नया उप-पैरा जोड़कर वाद में संशोधन की मांग की गई: –

> "वादी के पिता दलीप सिंह वाद-भूमि में सह-हिस्सेदार थे और चूंकि वह मर चुके हैं और वर्तमान वादी उनकी संपत्ति में सफल रहे हैं, इसलिए वे मुकदमे की भूमि में सह-हिस्सेदार हैं। तदनुसार, उन्हें इस आधार पर भी उपयुक्त भूमि में अग्रक्रय का बेहतर अधिकार प्राप्त है।."

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, वाद के पैरा 4 में विक्रेता के भाई का बेटा होने के नाते पूर्व-अनुभव के बेहतर अधिकार का दावा करने का आधार संबंध का था।

4. प्रतिवादी की ओर से आवेदन का विरोध किया गया था, जो अब मेरे सामने याचिकाकर्ता है, इस आधार पर कि संशोधन द्वारा वादी अग्रक्रय के बेहतर अधिकार का दावा करने के लिए एक नया आधार पेश करने की मांग कर रहे थे और इसलिए, उनके द्वारा की जा रही कार्रवाई का एक नया कारण है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि कार्रवाई के उस कारण के आधार पर लाया गया मुक़दमा संशोधन के लिए आवेदन की तारीख़ पर निराशाजनक रूप से समय से बाधित होगा

5. हालांकि, विद्वान उप-न्यायाधीश ने वादी के विद्वान वकील की दलीलों को स्वीकार कर लिया, जो विद्वान उप-न्यायाधीश के शब्दों में, निम्नानुसार थे: –

> "वादी के वकील ने तर्क दिया है कि मामला अलग होता अगर वादी विक्रेता के साथ अपने संबंधों को साबित करने में विफल रहे होते या रिश्ते की दलील छोड़ दी होती और केवल बिक्री के पूर्व-अनुभव के लिए सह-शेयरर की दलील पर भरोसा किया होता। उन्होंने कहा है कि चूंकि वादी अग्रक्रय के पहले आधार को छोड़े बिना अग्रक्रय की इस अतिरिक्त दलील को ले रहे हैं, इसलिए वे न तो अग्रक्रय के आधार को बदल रहे हैं और न ही एक अलग मामला बना रहे हैं, बल्कि केवल अग्रक्रय का एक नया आधार जोड़ रहे हैं, संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए।

विद्वान ट्रायल कोर्ट ने फैसले के ऑपरेटिव भाग में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि अग्रक्रय का एक नया आधार जोड़ा जा रहा था, लेकिन फिर निष्पक्ष खेल और न्यायपूर्ण और उचित होने के हित में इसकी अनुमति दी गई। की गई टिप्पणियां इस प्रकार थीं -

> " वर्तमान पूर्व निर्धारकों ने अपने पिता दलीप सिंह की मृत्यु के कारण कार्यवाही में कदम रखा है, और उन्होंने अग्रक्रय के नए आधार को जोड़ने के लिए वाद में संशोधन के लिए आवेदन किया है और संशोधन की अनुमति देना उचित और निष्पक्ष खेल के हित में होगा।"

6. मेरे समक्ष प्रतिवादी-याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि नीचे दिए गए न्यायालय का आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से परे है, क्योंकि न्यायालय के पास कार्रवाई के नए कारण या एक नया आधार जोड़ने की अनुमति देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जब मुकदमा, यदि कार्रवाई के नए कारण पर लाया जाता है, तो परिसीमा द्वारा वर्जित किया गया है। अग्रक्रय के बेहतर अधिकार का दावा मूल रूप से रिश्ते के आधार पर किया गया था, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि, यदि अंततः यह पाया जाता है कि इस आधार पर उनका कोई बेहतर अधिकार नहीं है, तो मुकदमा विफल हो जाएगा। यदि किसी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती है, तो वादी पंजाब प्री-एम्पोशन एक्ट, 1913 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 15 में दिए गए किसी अन्य आधार पर अग्रक्रयके बेहतर अधिकार के लिए अपने मुकदमे को बनाए रखने का दावा नहीं कर सकते हैं और ऐसे आधारों में से एक विक्रेता के साथ सह-हिस्सेदार होने का है। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जिस संशोधन की अनुमति दी गई है, वह उस आधार में पेश किया गया है जो पहले मौजूद नहीं था, और जिसका पहले लिए गए आधार से कोई संबंध नहीं है।

7. वादी-प्रतिवादियों की ओर से, उनके विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि संहिता की धारा 115 के तहत कार्य करने वाले इस न्यायालय के पास ट्रायल कोर्ट के किसी भी आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संशोधन की अनुमति देने या अस्वीकार करने का प्रश्न न्यायालय के विवेक का विषय है और यदि उस विवेकाधिकार का न्यायिक रूप से प्रयोग किया गया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उस विवेकाधिकार के प्रयोग में क्षेत्राधिकार की कोई कमी रही है या यह कि क्षेत्राधिकार का उपयोग अनियमित या अवैध तरीके से किया गया है और इस प्रकार इस न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप द्वारा बार-बार निर्धारित किए गए इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है।

8. *अन्य बातों के साथ-साथ* इस संबंध में विद्वान वकील द्वारा ***राधेश्याम और अन्य*** **बनाम** ***राम औतार और अन्य***[1]**, और एम.** ***के पलानीअप्पा चेट्टियाक्स और एक अन्य*** **बनाम** ***ए पेन्नुस्वामी पिल्लई***[2]

9. यहां सवाल पूरी तरह से अलग है। यदि यह एक ऐसा मामला था जहां संशोधन ने कार्रवाई का एक नया कारण नहीं उठाया था या, यदि इसने कार्रवाई का एक नया कारण उठाया था, तो यह समय के भीतर था और न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, या तो संशोधन की अनुमति दी या संशोधन की अनुमति देने से इनकार कर दिया, तो यह न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। वर्तमान मामले में कार्रवाई का एक नया कारण या पूर्व-मूल्यांकन के लिए मुकदमा बनाए रखने के लिए एक नया आधार जोड़ने और जोड़ने की अनुमति दी गई है, ऐसे समय में जब उस आधार पर लाया गया एक नया मुकदमा समय के साथ निराशाजनक रूप से वर्जित किया गया होगा और इसे न्यायिक तरीके से विवेक का प्रयोग नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से परे कार्य करने के रूप में लिया जाना चाहिए।

10. यह सवाल सीधे **शंकर सिंह** ***बनाम*** **चानन** ***सिंह मामले में मेहर सिंह***[3]**,** मुख्य न्यायाधीश *के सामने उठा*। रिपोर्ट के पृष्ठ 458 पर, संशोधन की अनुमति देने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए संहिता की धारा 115 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में तर्क पर चर्चा की गई थी और मैं विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई स्पष्ट टिप्पणियों को निम्नानुसार पुन: पेश करने से बेहतर कुछ नहीं कर सकता।: —

> "वादी के विद्वान वकील ने कहा कि जहां तक आदेश 6 (संहिता के) के नियम 17 का संबंध है, यह ट्रायल कोर्ट के विवेक का मामला है कि वह संशोधन की अनुमति दे या न दे और यदि उसने इस संबंध में विवेक का प्रयोग किया है, तो यह न्यायालय नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हालांकि, कानून की अदालत में निहित विवेकाधिकार हमेशा एक न्यायिक विवेक होता है और जहां यह विवेक का प्रयोग करता है, जैसा कि इस मामले में, सीमा के क़ानून के खिलाफ, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने न्यायिक रूप से विवेक का प्रयोग किया है। इसलिए, इसने इस संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है और इसलिए इस मामले पर नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के

[1] 1967 S.C.N. (No. 60). 51.

[2] 1970 (2) S.C. 290

3 1968 P.L.R 455

तहत विचार किया जा सकता है।

11. यह भी पूर्व-अनुभव का मामला था- वाद में, जैसा कि मूल रूप से दायर किया गया था, "संपार्श्विकता" के आधार पर अग्रक्रय के बेहतर अधिकार का दावा किया गया था। जब लिखित वक्तव्य में यह आपत्ति उठाई गई कि केवल संपार्श्विकता अधिनियम की धारा 15 के तहत कोई श्रेष्ठ अधिकार नहीं देती है, तो गलती का एहसास हुआ, और सटीक संबंध देकर संशोधन की मांग की गई। संशोधन को ट्रायल कोर्ट द्वारा अनुमति दी गई थी, हालांकि यह सीमा के बाद था, और इस आदेश को विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा रद्द कर दिया गया था- *अन्य बातों के साथ- साथ*: इसे पृष्ठ 457 पर निम्नानुसार देखा गया था: -

> उन्होंने कहा, 'जहां..... तक कृषि भूमि के संबंध में पूर्व अनुभव के अधिकार का संबंध है, संपार्श्विक संबंध अग्रक्रय का कोई आधार नहीं है... लेकिन वादी की तरफ से यह बताया गया है कि 1913 के पंजाब अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (ए) में दूसरा और तीसरा आधार विक्रेता के भाई या भाई के बेटे को और विक्रेता के पिता के भाई या पिता के भाई के बेटे को कृषि भूमि के संबंध में अग्रक्रय का अधिकार देता है और वादी के विद्वान वकील का कहना है कि वह संबंध वही है जो वादी का *आर्यन सिंह विक्रेता के साथ है*..... .....विद्वान वकील ने जोर देकर कहा कि वादी ने अपने संशोधन आवेदन में अपने संपार्श्विक संबंध की प्रकृति को समझाने के अलावा और कुछ नहीं किया है और जिस आधार पर उसने संपार्श्विक संबंध के आधार पर अग्रक्रय के अधिमान्य अधिकार का दावा किया है, उसे वाद में ही बताया गया है।

12. **रुलिया राम बनाम राम *चंद्र दास*[4]और चंदगी राम *बनाम* रबी दाऊ[5]** *का उल्लेख करने के बाद*, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने याचिका को खारिज कर दिया और निम्नानुसार टिप्पणी की: –

> "इस मामले में चानन सिंह वादी ने जो कुछ भी किया वह यह कहना था कि विक्रेता उसके संपार्श्विक हैं, लेकिन इस तरह के रिश्ते में 1913 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 15 अपने आप में अग्रक्रय का अधिकार नहीं देती है। एक विशेष परिभाषित संबंध अग्रक्रय का अधिकार देता है और यदि संबंध के आधार पर इस तरह के अधिकार का दावा किया जाता है, तो जाहिर है, 1913 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 15 में आधार के रूप में संदर्भित विशेष संबंध को कहा जाना चाहिए ..... : यदि सीमा की अवधि के बाद ऐसा

[4] AIR 1933 Lah 774
[5] AIR 1952 Pb.231

प्रयास किया जाता है, तो इसे उस अधिकार को पराजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो अग्रक्रय अधिकार रखने वाले व्यक्ति के दावे को पराजित करने के लिए गाहक को प्राप्त हुआ है; यह उस वैधानिक प्रावधान के दायरे में नहीं आता है जिस पर भरोसा किया जाता है।

13. मेरे सामने वर्तमान मामले के तथ्य विद्वान "मुख्य न्यायाधीश" के सामने के तथ्यों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हैं। यहां मूल रूप से लिये गये aadhar और उन आधारों के बीच कोई संबंध नहीं है जिसे जोड़ने की मांग की जाती है। यह पहले से लिए गए आधारों को समझाने का प्रयास नहीं है। मूल रूप से दावा केवल रिश्ते के आधार पर किया गया था। और इस बात पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि, यदि वह संबंध साबित नहीं होता है, तो वादी का मुकदमा विफल होना तय है, लेकिन, यदि संशोधन की अनुमति दी जाती है, तो, भले ही वादी रिश्ते के सवाल पर विफल हो जाते हैं, वे सह-हिस्सेदार होने के दूसरे आधार पर वापस आ सकते हैं जो वे सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद पहली बार ले रहे हैं। विद्वान मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियां वर्तमान मामले के तथ्यों पर कहीं अधिक बल के साथ लागू होती हैं। यदि संशोधन की तारीख पर सह-शेयरर-शिप के आधार पर मुकदमा लाया गया होता, तो यह स्पष्ट रूप से समय तक वर्जित कर दिया गया होता।

14. प्रतिवादियों की ओर से के मामले में ***बकंता सिंह और अन्य*** **बनाम** ***मेहर सिंह और अन्य***[6] गुरदेव सिंह न्यायमूर्ति के फैसले का संदर्भ दिया गया था। वहां अग्रक्रय के बेहतर अधिकार का दावा इस आधार पर किया गया था कि वादी विक्रेता का भाई था। लिखित बयान में की जा रही आपत्ति पर, कि वादी उसका भाई नहीं था, वादी ने गलती को सुधारने के लिए संशोधन की मांग की और 'विक्रेता का भाई' शब्दों के स्थान पर 'विक्रेता के पिता का भाई' शब्द रखना चाहा। ट्रायल कोर्ट ने संशोधन की अनुमति दी और इस अदालत में एक संशोधन लाया जा रहा है, गुरदेव सिंह जे, ने निम्नानुसार कहा: —

"…. दोनों समय वाद मूल रूप से तैयार किया गया था और जब बाद में इसमें संशोधन किया गया था, तो वादी विक्रेताओं के साथ अपने संबंधों पर अग्रक्रय के अपने दावे को आधार बना रहा था। हालांकि मूल रूप से उनके द्वारा बताए गए संबंध ने उनके मामले को धारा 15 I (1) (बी) के खंड के तहत लाया, बाद में संशोधन के परिणामस्वरूप यह धारा 15: (1) (बी) के खंड तीसरे के तहत आता है, संशोधन की मांग करने वाले वादी ने दावा किया कि यह टाइपिंग या लिपिकीय

[6] 1970 P.L.R. 37

गलती के कारण था कि वाद के पैराग्राफ 3 में 'पिता' शब्द को छोड़ दिया गया था।"

15. इस मामले का वर्तमान मामले पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि मांगा गया संशोधन किसी टाइपिंग या लिपिकीय गलती के सुधार के लिए है और वास्तव में, दूसरे आधार का पहले आधार से कोई संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि यह भी अधिनियम की धारा 15 के तहत आधारों में से एक है।

16. इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी संदर्भ दिया गया था। ***के. गुप्ता एंड संस लिमिटेड*** **बनाम** ***दामोदर घाटी निगम***[7]। उस मामले में एक अनुबंध में एक खंड था कि यदि प्रचलित श्रम दर में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होती है, तो ठेकेदार आनुपातिक बढ़ी हुई दरें वसूलने का हकदार होगा। श्रम दर बढ़कर 20 प्रतिशत हो गई है, उन्होंने दावा किया कि उनकी निविदा दरों में उस हद तक वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, इस मामले को न्यायालय में ले जाया गया। दायर वाद इस घोषणा के लिए था कि खंड की उचित व्याख्या पर, वह निविदा दरों पर 20 प्रतिशत की वृद्धि का हकदार था। • मुकदमा डिक्री किया गया था, लेकिन अपील में इसे विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 42 के मद्देनजर सुनवाई योग्य नहीं माना गया था। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय से अनुबंध के पैसे या ऐसी अन्य राशि के लिए डिक्री के लिए एक अतिरिक्त राहत जोड़कर वाद में संशोधन करने की अनुमति मांगी, जो उचित खाते पर देय पाया जाना था। संशोधन से इनकार किए जाने के बाद, मामले को संविधान के अनुच्छेद 133 (1) (ए) के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील में लिया गया था और इसे निम्नानुसार बहुमत से माना गया था: -

उन्होंने कहा, ' संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए. यह मुकदमा अनुबंध पर था, जिसमें इसके तहत पार्टियों के अधिकारों के निर्णय के लिए केवल खंड की व्याख्या की मांग की गई थी और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। कार्रवाई का कारण अनुबंध ही था जिस पर मुकदमा आधारित था। संशोधन में कार्रवाई के एक ही कारण, अर्थात् एक ही अनुबंध के आधार पर एक दावा पेश करने की मांग की गई और कोई नया मामला या तथ्य पेश नहीं किया गया।

17. सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप ने इस सवाल पर बहुत जोर दिया कि दावा *कार्रवाई के एक ही कारण*

[7] AIR 1967 S.C.96

पर आधारित था। वास्तव में, उन्होंने पैराग्राफ (7) और (8) में निम्नानुसार अवलोकन किया: –

"(7) ..... इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामान्य नियम यह है कि एक पार्टी को एक नया मामला या कार्रवाई का एक नया कारण स्थापित करने के लिए संशोधन द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, खासकर जब नए मामले या कार्रवाई के कारण पर मुकदमा प्रतिबंधित होता है: ***वेल्डन* बनाम बी *नेले***[8]। लेकिन यह भी अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि जहां संशोधन कार्रवाई के एक नए कारण को जोड़ने या एक अलग मामले को उठाने का गठन नहीं करता है, लेकिन समान तथ्यों के लिए एक अलग या अतिरिक्त दृष्टिकोण से अधिक नहीं है, तो सीमा की वैधानिक अवधि समाप्त होने के बाद भी संशोधन की अनुमति दी जाएगी ।.

(8) अंतिम रूप से उल्लिखित नियम के प्रमुख कारण हैं, पहला, और दूसरा, कि एक पक्ष को परिसीमा के क़ानून पर भरोसा करने का सख्त अधिकार नहीं है, जबकि संशोधन द्वारा जो कुछ लाने की मांग की जा रही है, उसे संक्षेप में कहा जा सकता है कि यह पहले से ही संशोधन के लिए मांगी गई दलील में है.....

18. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जिस याचिका को अब जोड़ने की मांग की जा रही है, उसे 'सार रूप में पहले से ही दलील में होना' कहा जा सकता है और इसका जवाब नकारात्मक है. सह-भागीदारी का आधार मूल दलील में इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है।
19. इस न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट अधिकार को ध्यान में रखते हुए, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि नीचे दिए गए न्यायालय ने न्यायिक तरीके से अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं किया था और एक नए आधार की अनुमति देने में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया था, या अग्रक्रय के बेहतर अधिकार का दावा करते हुए, ऐसे समय में जब उस आधार पर आधारित मुकदमा समय पर वर्जित कर दिया गया होता ।
20. इसलिए, मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं, नीचे दिए गए न्यायालय के आदेश को रद्द करता हूं और वाद में संशोधन की मांग करने वाले आवेदन को खारिज करता हूं। ट्रायल कोर्ट सभी संभावित अभियानों के साथ असंशोधित वाद के आधार पर मामले पर आगे बढ़ेगा। इस मामले का रिकॉर्ड तुरंत संबंधित अदालत को वापस भेजा जाएगा। वकील पार्टियों को आगे की कार्यवाही के लिए 1 मार्च 1971 को नीचे की अदालत में पेश होने का निर्देश देगा। इस याचिका की लागत

[8] 1887 19 Q.B.D 394

प्रतिवादियों द्वारा वहन की जाएगी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ओमेश

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी